आकाशवाणी केन्द्र शिमला
21.03.2026 / प्रादेशिक समाचार / 19:45बजे

मुख्य समाचार

- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026–27 का बजट किया पेश– 54 हज़ार 2 सौ 98 करोड़ का होगा बजट।
- मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों का 20 से लेकर 50 प्रतिशत तक वेतन अगले 6 महीने तक के लिए स्थगित।
- वित्तीय संकट के बावजूद मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कीं कई घोषणाएं– दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी सहित विभिन्न श्रेणियों के पैरा वर्करों का बढ़ा मानदेय।

और

- भाजपा ने बजट को दिशाहीन दिया करार– कांग्रेस ने बताया जनहितैषी।

मुख्यमंत्री–बजट

हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2026–27 का बजट 54 हज़ार 2 सौ 98 करोड़ रुपये होगा। ये बजट वर्ष 2025–26 की तुलना में 3 हज़ार 5 सौ 86 करोड़ रुपये कम होगा। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य का अगले वित्त वर्ष का बजट पेश किया। ये उनका लगातार चौथा बजट है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आरडीजी बंद होने के कारण बजट का आकार बीते साल की तुलना में कम हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026–27 में प्रदेश की राजस्व प्राप्तियां 40 हज़ार 3 सौ 61 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है जबकि कुल राजस्व व्यय 46 हज़ार 9 सौ 38 करोड रुपए रहना अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 6 हज़ार 5 सौ 77 करोड़ रुपए अनुमानित है जबकि राजकोषीय घाटा 9 हज़ार 6 सौ 98 करोड़ रुपए अनुमानित है जो कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 3 दशमलव 9–4 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बजट के सौ रुपये में से वेतन पर 27 रुपये, पेंशन पर 21 रुपये, ब्याज अदायगी पर 13 रुपये, कर्ज अदायगी पर 9 रुपये, स्वायत्त संस्थाओं के लिए ग्रांट पर 10 रुपये जबकि 20 रुपये पूंजीगत कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर खर्च होंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के गंभीर आर्थिक संकट को देखते हुए अपने वेतन का 50 प्रतिशत अगले 6 महीने के लिए स्थगित करने और उपमुख्यमंत्री व मंत्रियों का 30 प्रतिशत वेतन अगले 6 महीने के लिए स्थगित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विधायकों और सभी निगमों बोर्डों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, सलाहकारों, व ओएसडी का 20 प्रतिशत वेतन अगले 6 महीने के लिए स्थगित रहेगा। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिवों का 30 प्रतिशत वेतन अगले 6 महीने के लिए स्थगित करने का ऐलान किया। इसी तरह सचिवों से लेकर

विभागाध्यक्षों का 20 प्रतिशत वेतन अगले 6 महीने के लिए स्थगित रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीजीपी और अतिरिक्त डीजीपी के वेतन का भी 30 प्रतिशत वेतन अगले 6 महीने के लिए स्थगित रहेगा, जबकि आईजी स्तर से लेकर एसपी स्तर तक के अधिकारियों का 20 प्रतिशत वेतन अगले 6 महीने के लिए स्थगित रहेगा। इसके अतिरिक्त वन विभाग में वन प्रमुख, पीसीसीएफ और एडिशनल पीसीसीएफ का भी 30 प्रतिशत जबकि सीसीएफ से लेकर डीएफओ स्तर तक के अधिकारियों का 20 प्रतिशत वेतन अगले 6 महीने तक स्थगित रहेगा। मुख्यमंत्री ने ग्रुप ए और बी के राजपत्रित अधिकारियों के वेतन का 3 प्रतिशत अगले 6 महीने के लिए स्थगित रहेगा, जबकि ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को वेतन बिना किसी कटौती के पहले की तरह के मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश उच्च न्यायालय से भी आग्रह किया कि वह अपने स्तर पर इस तरह के कदम उठाने पर विचार कर सकता है ताकि प्रदेश के प्रति एकता और जिम्मेदारी की भावना को और मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह केवल अस्थाई व्यवस्था है और जैसे ही प्रदेश की वित्तीय स्थिति बेहतर होगी यह राशि वापस कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि राज्य की आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रहे। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस चुनौतीपूर्ण समय में सभी जनप्रतिनिधि, न्यायपालिका अधिकारी और कर्मचारी राज्यहित में पूरा सहयोग देंगे।

विपक्ष हंगामा

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू द्वारा विधानसभा में बजट प्रस्तुत करने के आरंभ में ही उन्होंने आरडीजी बंद होने का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने आरडीजी के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर सरकार का साथ नहीं देने का आरोप लगाया। इस पर विपक्ष मुख्यमंत्री के कुछ शब्दों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए शोरगुल करने लगा। बाद में विपक्षी सदस्य नारे लगाते हुए सदन से बाहर चले गए। और ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता.....

डिस्पैच– शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के आज चौथे दिन विपक्षी दल भाजपा सदन के बाहर और अंदर सरकार पर हावी होता दिखाई दिया। मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण शुरू करते ही आरडीजी बंद करने का ज़िक्र के दौरान कुछ शब्दों के इस्तेमाल पर विपक्षी सदस्य नाराज़ दिखे और इस पर कड़ी आपत्ति जताई। इस दौरान पूरा विपक्ष अपनी सीट पर खड़ा होकर शोरगुल करने लगा और बाद में सदन के बीचों–बीच नारे लगाते हुए पहुंच गया। भारी हंगामे के कारण मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को अपना बजट भाषण बीच में ही रोकना पड़ा। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विपक्ष से अपनी सीटों पर जाने को कहा, लेकिन जब विपक्ष हंगामे पर अड़ा रहा तो विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। इस बीच पूरा विपक्ष सदन से बाहर चला गया। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही फिर से शुरू कर दी, इस पर विपक्ष भी फिर से सदन में लौट आया और विधानसभा अध्यक्ष के फैसले का विरोध करने लगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि वह अपने फैसले को रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन जब विपक्ष नहीं माना तो उन्होंने मुख्यमंत्री को बजट भाषण फिर से शुरू करने को कहा। मुख्यमंत्री ने सदन के भारी हंगामे के बीच ही बजट भाषण शुरू कर दिया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्था दी की मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण में कहे गए आपत्तिजनक शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया गया है। इसके बाद हंगामा शांत हुआ और मुख्यमंत्री ने अपना बजट भाषण फिर से पढ़ना शुरू किया।

रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार शिमला.....

बजट घोषणाएं

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण में समाज के सभी वर्गों के लिए कई घोषणाएं भी कीं। अपने बजट भाषण में उन्होंने गंभीर वित्तीय संकट के बावजूद वर्ष 2016 से पूर्व के सभी पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को बकाया पेंशन और पारिवारिक पेंशन के पूरे एरियर के भुगतान की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को अगले वित्त वर्ष से साल में दो बार 31 मार्च और 30 सितंबर को निर्धारित सेवाकाल पूर्ण करने पर नियमित करने की भी घोषणा की। सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने दिहदीदारों की दिहाड़ी में 25 रुपये और आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 13 हज़ार 7 सौ 50 रुपए प्रति माह वेतन देने का ऐलान किया। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं और आशा वर्करों के मानदेय में एक–एक हजार रुपये की वृद्धि करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मिड डे मील वर्करों, वॉटर कैरियर, जल रक्षकों, जल शक्ति व लोक निर्माण विभाग के मल्टीपरपज वर्करों, पैरा फिटर व पंप ऑपरेटर, पंचायत चौकीदारों, राजस्व चौकीदारों, राजस्व लंबरदारों, एसएमसी शिक्षकों, आईटी शिक्षकों, एसपीओ और पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्करों के मानदेय में भी हर महीने 5–5 सौ रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए गाय के दूध का खरीद मूल्य 51 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये और भैंस के दूध का खरीद मूल्य 61 रुपये से बढ़ाकर 71 रुपये करने का ऐलान किया। सुखविंद्र सिह सुक्खू ने प्राकृतिक रूप से उगाई गई गेहूं का समर्थन मूल्य 60 रुपये से बढ़कर 80 रुपये प्रति किलो, मक्का का 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये, पांगी के जौ का समर्थन मूल्य 60 से बढ़ाकर 80 रूपये करने और हल्दी का समर्थन मूल्य 90 से बढ़ाकर डेढ़ सौ रुपए प्रति किलो करने की घोषणा की। उन्होंने अदरक को भी समर्थन मूल्य के तहत 30 रूपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में एक लाख परिवारों को **मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना** के तहत लाया जाएगा। उन्होंने इन परिवारों को 3 सौ यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की।

भाजपा प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट की भाजपा ने जहां आलोचना की है वहीं कांग्रेस ने इसे जनहितेषी करार दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित भाजपा सांसदों व अन्य पार्टी नेताओं ने कहा कि बजट का आकार इस बार कम हो गया है जिससे स्पष्ट हो गया है कि सरकार ने अपनी वित्तीय विफलता को स्वीकार कर लिया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे निराश और दिशाहीन बजट है।

पत्रकार वार्ता

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा को हिमाचल विरोधी बताते हुए कहा है कि भाजपा न ही आपदा में प्रदेश के लोगों के साथ खड़ी हुई और न ही आरडीजी के मामले में सरकार का साथ दिया। मुख्यमंत्री ने बजट को ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि पहली बार किसी बजट में वेतन में कटौती की गई है।